तीन माह में मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करे सरकार: हाईकोर्ट

अदालत ने कहा- महत्वपूर्ण पद लंबे समय तक खाली नहीं रखे जा सकते; जनवरी में होगी अगली सुनवाई

रांची|झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य मानवाधिकार आयोग में लंबे समय से रिक्त अध्यक्ष, सदस्यों सहित अन्य पदों पर नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को समय-सीमा तय कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद सरकार को तीन माह के भीतर आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों सहित अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के प्रमुख पदों को लंबे समय तक रिक्त नहीं रखा जा सकता। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। मामला आयोग में लंबे समय से रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सोनल तिवारी ने अदालत को बताया कि अध्यक्ष का पद वर्ष 2018 से रिक्त है। अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली रहने से मानवाधिकार से जुड़े मामलों की सुनवाई और आयोग के कामकाज पर असर पड़ रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य में मानवाधिकार से संबंधित कई मामले लंबित हैं। ऐसे में पर्याप्त पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से मामलों के निपटारे की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। प्रार्थी की ओर से रिक्त पदों को जल्द भरने का आग्रह किया गया।

माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा मामला: रिस्पांस शीट नहीं खुली तो कोर्ट में होगा पोर्टल का लाइव लॉग-इन

रांची| माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की रिस्पांस शीट और आंसर-की डाउनलोड नहीं होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने तकनीकी जांच का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के कंप्यूटर एवं आईटी विशेषज्ञों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। अदालत तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में संबंधित अभ्यर्थियों की ई-मेल आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉग-इन कर स्थिति की जांच करेगी। देखा जाएगा कि अभ्यर्थियों की रिस्पांस शीट और आंसर-की पोर्टल पर उपलब्ध है या नहीं और उपलब्ध होने की स्थिति में उसे डाउनलोड किया जा सकता है या नहीं। मामला विकास पांडेय एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि परीक्षा में शामिल होने के बाद अभ्यर्थियों ने जेएसएससी की वेबसाइट पर अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन कर रिस्पांस शीट और आंसर-की डाउनलोड करने की कोशिश की। लेकिन पोर्टल पर 'यूजर डज नॉट एग्जिस्ट' संदेश दिखाई दिया। जेएसएससी ने ई-मेल या पासवर्ड गलत होने की जताई संभावना जेएसएससी की ओर से इस मामले में पहले ही शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। आयोग ने अपने जवाब में संभावना जताई है कि अभ्यर्थियों ने ई-मेल आईडी या पासवर्ड सही तरीके से दर्ज नहीं किया होगा, जिसके कारण यह संदेश आया हो।

बर्खास्त जैप-8 सिपाही को 8 साल की सेवा निरंतरता, बकाया वेतन भी मिलेगा

रांची| झारखंड हाईकोर्ट ने जैप-8 पलामू के सिपाही जितेंद्र कुमार को बर्खास्तगी के बाद पुनर्बहाली के मामले में राहत दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने 28 नवंबर 2015 से 13 अक्टूबर 2023 तक की करीब आठ साल की अवधि को सेवा में निरंतरता मानते हुए बकाया वेतन समेत सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस अवधि को 'नो वर्क, नो पे' के आधार पर बिना वेतन रखने और असाधारण अवकाश मानने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया। संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड का सत्यापन कर बकाया राशि समेत सभी लाभ 12 सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया गया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नेहा भारद्वाज ने पक्ष रखा। जितेंद्र के खिलाफ 30 दिसंबर 2014 को विभागीय आरोप पत्र गठित हुआ था। उन पर फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने और नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप था। आरोप प्रमाणित होने के बाद 28 नवंबर 2015 को उन्हें बर्खास्त किया गया था।

नगर निगम को बिना अनुमति लगे होर्डिंग व यूनिपोल हटाने की छूट

रांची| झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में आउटडोर विज्ञापन से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और रांची नगर निगम को दो सप्ताह के भीतर आउटडोर एडवरटाइजिंग पॉलिसी रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में झारखंड स्टेट आउटडोर एडवरटाइजिंग एसोसिएशन समेत संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने अंतरिम तौर पर रांची नगर निगम को बिना अनुमति लगाए गए यूनिपोल और विज्ञापन बिलबोर्ड हटाने की छूट दी है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगे विज्ञापन बोर्ड हटाने या उन्हें 12 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कम ऊंचाई पर लगे बोर्ड वाहन चालकों के लिए ब्लाइंड स्पॉट बना सकते हैं और दुर्घटना का खतरा बढ़ा सकते हैं। अदालत ने डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभों पर विज्ञापन की ऊंचाई को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए थे।

बिजली चोरी के खिलाफ हुई छापेमारी, 497 पर प्राथमिकी

रांची| जेबीवीएनएल के द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ रांची सहित पूरे राज्य में अभियान चलाया गया। निगम मुख्यालय के निर्देश पर कुल 119 विशेष टीमों का गठन किया गया था। इस दौरान राज्यभर के 3510 परिसरों पर छापे मारे गए। इस दौरान 497 में बिजली चोरी पकड़ी गई। मौके पर ही भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की सुसंगत धाराओं के तहत इन सभी के खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस पूरी कार्रवाई में कुल 96.44 लाख रुपए की राशि वसूली की गई। निगम ने राज्य के सभी नागरिकों और उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि आपके आसपास कोई बिजली की चोरी कर रहा है, तो उसकी जानकारी महाप्रबंधक (एपीटी) के मोबाइल नंबर 94311-35515 पर व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए दें।

अपर बाजार में ग्रिल काटकर दुकान में घुसे चोर, 2.09 लाख रुपए की चोरी

क्राइमरिपोर्टर | रांची

कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपर बाजार में चोरों ने एक प्लास्टिक दुकान को निशाना बनाते हुए 2.09 लाख रुपए से अधिक की नकदी की चोरी कर ली। दुकान संचालक ने कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन के अनुसार, अपर बाजार ईस्ट मार्केट रोड स्थित मेसर्स सुजाता प्लास्टिक के संचालक राहुल शर्मा ने बताया कि 17 सितंबर की रात करीब आठ बजे दुकान बंद कर वह घर चले गए थे। 18 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर सामान अस्त-व्यस्त मिला। जांच करने पर दुकान से 2,09,880 रुपए नकद गायब मिले। दुकान संचालक राहुल शर्मा के मुताबिक चोर दुकान के ऊपरी तल पर जाने वाली ग्रिल और लकड़ी के पार्टिशन को काटकर अंदर दाखिल हुए। मौके पर लोहे की ग्रिल और लकड़ी के टुकड़े जमीन तथा सीढ़ियों पर बिखरे मिले। सीढ़ियों पर एक लोहे का साबल भी पड़ा हुआ था। इससे आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने ग्रिल और लकड़ी का पार्टिशन तोड़ने के लिए औजार का इस्तेमाल किया। पुलिस घटनास्थल की जांच, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और संदिग्धों की गतिविधियों के आधार पर चोरों का सुराग तलाश रही है।

सीयूजे... बंधु पर सुरक्षा अधिकारी के साथ मारपीट का लगाया आरोप

रांची| केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (सीयूजे) के मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय में शुक्रवार को विश्वविद्यालय अधिकारियों और पूर्व विधायक बंधु तिर्की के बीच विवाद का मामला सामने आया है। विवि के सुरक्षा अधिकारी तरुण कुमार ने नैयर अंसारी, विधायक बंधु तिर्की समेत अन्य लोगों पर गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है। सुरक्षा अधिकारी ने रजिस्ट्रार को दिए आवेदन में घटना की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कराने और मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज कराने की मांग की है। सुरक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार घटना करीब 11:51 बजे मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय के कक्ष संख्या 108-ए में हुई। इधर, विधायक बंधु तिर्की ने स्थानीय लोगों की जमीन और रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के लिए जिन लोगों की जमीन गई है, उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। कहा कि कुछ स्थानीय लोगों को गार्ड की नौकरी मिली, लेकिन उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है।

अपर बाजार की दो दुकानों में चोरी पर चैंबर ने जताया आक्रोश

रांची | राजधानी रांची के ईस्ट मार्केट रोड (अपर बाजार) में शुक्रवार को दो दुकानों में हुई चोरी से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। घटना पर संज्ञान लेते हुए झारखंड चैंबर के सह-सचिव अमित शर्मा व कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल ने घटनास्थल का जायजा लिया। चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने पीड़ित कारोबारियों से बात की और कोतवाली थाना प्रभारी से दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में चोरी की घटना सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। चैंबर ने पुलिस से क्षेत्र में गश्ती और सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया है।

जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा गड़बड़ी मामला

अभय तिवारी की पत्नी व भाई की जमानत याचिका खारिज

रांची| जेपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली से जुड़े सीआईडी केस में अपर न्यायायुक्त-1 योगेश कुमार की अदालत ने आरोपी सुषमा कुमारी और उसके देवर अक्षय कुमार तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुषमा मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी की पत्नी है, जबकि अक्षय उसका भाई है। दोनों 19 अगस्त से न्यायिक हिरासत में हैं। सुषमा की ओर से दलील दी गई थी कि उसे केवल पति अभय तिवारी की पत्नी होने के कारण मामले में आरोपी बनाया गया है। बचाव पक्ष ने उसकी ढाई साल की बच्ची की स्थिति का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर जमानत मांगी थी। सीआईडी ने केस डायरी में उसके खिलाफ पति की गतिविधियों से जुड़े बयान, सीडीआर, होटल रिकॉर्ड, परीक्षा से पहले बोकारो के दुग्दा में मौजूदगी और कथित तौर पर दो लाख रुपए के लेन-देन का उल्लेख किया। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि उसने साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल फोन नष्ट किया।

वहीं, अक्षय की ओर से कहा गया कि केवल भाई अभय से रिश्ते के कारण फंसाया गया है। उसकी ओर से गंभीर हृदय रोग का हवाला देते हुए इलाज के लिए जमानत मांगी गईयी। सीआईडी ने आरोप लगाया कि सीजीएल-2023 परीक्षा से एक दिन पहले अक्षय बोकारो पहुंचा था। उसके सीडीआर, यात्रा विवरण और बयान से कथित परीक्षा 'सेटिंग' से जुड़ाव सामने आता है। जांच एजेंसी के अनुसार, उसने सीजीएल-2023 और 14वीं जेपीएससी पीटी में कथित सेटिंग से सफलता हासिल की।

मोकामा होकर चलनेवाली कई ट्रेनें रद्द, कई के रूट बदले

रांची|नए मोकामा रेल पुल से नियमित ट्रेनों के परिचालन को लेकर 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक लिए जा रहे रेलवे ब्लॉक का सीधा असर झारखंड के रेल यात्रियों पर पड़ने वाला है। झारखंड से उत्तर बिहार को जोड़ने वाली 18181 टाटानगर-थावे एक्सप्रेस टाटानगर से 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रद्द रहेगी, वहीं वापसी में 18182 थावे-टाटानगर एक्सप्रेस थावे से 1, 3 और 4 अक्टूबर को नहीं चलेगी। इसके अलावा झारखंड के धनबाद और संताल परगना सीमा से जुड़ी 13507/13508 आसनसोल-गोरखपुर और 13509/13510 आसनसोल-गोंडा एक्सप्रेस भी 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच विभिन्न तिथियों पर रद्द रहेंगी। दूसरी ओर, झारखंड-ओडिशा मार्ग पर चलने वाली 15027/15028 संबलपुर-गोरखपुर-संबल पुर मैथ एक्सप्रेस 25 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच परिवर्तित मार्ग किऊल-मुंगेर-बरौनी के रास्ते चलाई जाएगी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा :
थाना चौक, रामगढ़, झारखंड | मो. नंबर 8114595921

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना, परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 संगठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम- 8(6) के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रय का ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा जन साधारण को सामान्यतः एवं ऋणी(यों), बंधककर्ता(ों) तथा जमानतदारों को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित बंधक / प्रभारित अचल संपत्ति प्रतिभूत ऋणदाता के कब्जे में है, जिसका **"जहाँ है, जैसी है, जो कुछ भी है"** के आधार पर निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली के लिए विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणकर्ताओं / बंधककर्ता / जमानतदार / सुरक्षित संपत्ति / बकाया राशि / आरक्षित मूल्य / ई-नीलामी तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नवर्णित है :

क्र. सं.	ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण, जिसमें ज्ञात अदिभार (यदि कोई हो) भी शामिल है	कुल बकाया राशि/ ई-नीलामी की तिथि/ ई-नीलामी का समय	आरक्षित मुल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (रचनात्मक/भौतिक) / सम्पत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय
01	**मैसर्स त्रिमूर्ति ट्रेडिंग प्रोपराइटर - श्री सुधांशु कुमार श्रीवास्तव**, बाजार टांड़, एमएमटी ग्राउंड के पास, रामगढ़, झारखंड - 829122 **श्री सुधांशु कुमार श्रीवास्तव (प्रोपराइटर, मैसर्स त्रिमूर्ति ट्रेडिंग)**, पिता - श्री तानिक लाल, मकान नं.- 30, चट्टी बाजार, सेंट्रल मार्केट के पास, वार्ड नं.- 8, रामगढ़, झारखंड - 829122	भूमि के सभी भाग, जिसका क्षेत्रफल 03 डिसमिल है, प्लॉट नं.- 2331, खाता नं.- 54, थाना नं.- 82, परसोतिया, मौजा- रामगढ़, थाना- रामगढ़, श्री सुधांशु कुमार श्रीवास्तव, पिता- श्री तानिक लाल, के स्वामित्व में है। **भूमि विलेख संख्या 640 के अनुसार सीमाएँ :** उत्तर: दयालु महतो, दक्षिण: रास्ता, पूर्व: सुरेश यादव, पश्चिम: विश्वनाथ प्रसाद	**₹ 20,07,474.88** के अतिरिक्त 31.01.2026 से अप्रयुक्त ब्याज एवं प्रभार, जैसा कि मांग सूचना के अनुसार है, तथा संविदात्मक बकाया रु. 22,38,274.85, के साथ उस पर लगने वाली लागत एवं ब्याज। **22.10.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 18,90,000/- / रु. 1,89,000/- / रु. 18,900/-	**सांकेतिक कब्जा** / **21.10.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**
02	**श्रीमती गीता देवी (ऋणकर्ता)** पति - श्री गणेश प्रसाद, पता - डाटमा मोड़, कुजू, कोल्ड स्टोरेज के पास, पोस्ट - कुजू, थाना - मांडू, जिला - रामगढ़, झारखंड - 825316	भूमि के सभी भाग, जिसका क्षेत्रफल 25½ + 25½ + 25½ डिसमिल, ग्राम- चोरगांव, थाना- महुआटांड़, थाना नं.- 06, प्लॉट नं.- 200, खाता नं.- 06, अंचल- गोमिया, जिला- बोकारो में स्थित है तथा श्रीमती गीता देवी के नाम पर दर्ज है। **भूमि विलेख संख्या 102 के अनुसार सीमाएँ :** उत्तर: पक्की सड़क, दक्षिण: पड़ती कदीम, पूर्व: बालेश्वर साव, पश्चिम: क्रेता **भूमि विलेख संख्या 103 के अनुसार सीमाएँ :** उत्तर: पक्की सड़क, दक्षिण: पड़ती कदीम, पूर्व: क्रेता, पश्चिम: क्रेता **भूमि विलेख संख्या 104 के अनुसार सीमाएँ :** उत्तर: पक्की सड़क, दक्षिण: पड़ती कदीम, पूर्व: क्रेता, पश्चिम: पड़ती कदीम	**₹ 15,06,350.55** के अतिरिक्त 21.09.2023 से अप्रयुक्त ब्याज एवं प्रभार, जैसा कि मांग सूचना के अनुसार है, तथा 02.11.2025 तक संविदात्मक बकाया रु. 20,97,429.65, के साथ उस पर लगने वाली लागत एवं ब्याज। **22.10.2026 अपराह्न 02:00 से अपराह्न 06:00 बजे तक**	रु. 34,65,000/- / रु. 3,46,500/- / रु. 34,650/-	**सांकेतिक कब्जा** / **21.10.2026 पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 03:00 बजे तक**

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल **https://baanknet.com** देखें।
इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर **8114595921** पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : रामगढ़
दिनांक: 18.09.2026

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

ह०/ प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा, रामगढ़

सत्य सांगू, बिनधास्त
दिव्य मराठी

दैनिक भास्कर
की एडिटर दीप्ती राउत को
द स्टेट्समैन अवॉर्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग 2025
में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई



दीप्ती राउत
दैनिक दिव्य मराठी, नासिक

ग्रामीण महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत को उजागर करने वाली अपनी प्रभावशाली रिपोर्टिंग में दीप्ती राउत ने बताया कि कैसे जननी सुरक्षा योजना पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद महाराष्ट्र की सीमा से लगे गांवों में महिलाएं तीर-कमान, बांस की टोकरी और कपड़ों के सहारे प्रसव कराने को मजबूर थीं।

रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जनहित याचिका दर्ज हुई और स्वास्थ्य विभाग को जांच के निर्देश दिए गए।

जनसरोकार से जुड़ी सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता के इस उत्कृष्ट कार्य तथा 'द स्टेट्समैन अवॉर्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग 2025' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर दीप्ती राउत को पुनः हार्दिक बधाई।

दैनिक भास्कर समूह

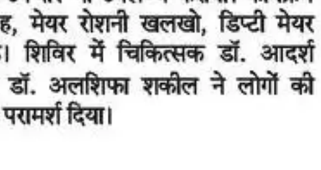
न्यूज ब्रीफ

मृत खलासी के परिजनों को 2.75 लाख रु. की मदद



रांची| बिरसा मुंडा बस स्टैंड प्रांगण में बस चालक कल्याण संघ द्वारा लगातार छठे वर्ष विश्वकर्मा पूजा, लंगर एवं माता के जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ ने दिवंगत खलासी (श्री साईं बस) हदीस अंसारी के परिवार को 2.75 लाख रुपए की आर्थिक मदद व सिलाई मशीन प्रदान की। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह, संघ अध्यक्ष विश्वनाथ मिश्रा व सचिव राणा बजरंगी सिंह ने मृतक के परिजनों को रुपए और मशीन दिए। मौके पर संजू चौहान, मो. महफूज, रितेश मिश्रा, राकेश सिंह, लाडला खान, राम विनय यादव, राजन घोष व सोनू शंकर महतो मौजूद थे।

रांची एयरपोर्ट पर लोकनृत्य से यात्रियों का स्वागत



रांची| बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची में यात्री सेवा अभियान 2026 एवं स्वच्छता ही सेवा 2026 का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार के सहयोग से यात्रियों का पारंपरिक करसा लोकनृत्य के साथ स्वागत किया गया। झारखंड की लोक संस्कृति की आकर्षक प्रस्तुति ने यात्रियों के स्वागत को खास बना दिया। कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम्' का गायन किया। वहीं, स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एयरपोर्ट परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने, कचरे के उचित प्रबंधन और यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। अभियान के तहत एयरपोर्ट परिसर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वच्छ और बेहतर एयरपोर्ट परिसर बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया।

मेगा स्वास्थ्य शिविर में 150 मरीजों की नि:शुल्क जांच



रांची|सुखदेवनगर थाना के समीप जनता फ्लैट परिसर में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मंत्री अमित कुमार सिंह की ओर से मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने किया। शिविर में 150 से अधिक लोगों की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। चिकित्सकों ने मरीजों को आवश्यक परामर्श देने के साथ उपचार भी उपलब्ध कराया। कार्यक्रम में रांची के विधायक सीपी सिंह, मेयर रोशनी खलखो, डिप्टी मेयर नीरज कुमार आदि मौजूद रहे। शिविर में चिकित्सक डॉ. आदर्श शाही, डॉ. सोमैल अथर और डॉ. अलशिफा शकील ने लोगों की स्वास्थ्य जांच कर चिकित्सकीय परामर्श दिया।

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
के निर्देशानुसार
जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), कोडरमा
के द्वारा आयोजित
मध्यस्थता अभियान
राष्ट्र के लिए - 3.0
(नि:शुल्क, सुलभ एवं शीघ्र न्याय)
दिनांक 01 अक्टुबर 2026, पूर्वाह्न 10:30 बजे से
दिनांक 30 दिसम्बर 2026 तक

निस्तारण वाले मामले
- वैवाहिक मामले जिनमें DV ACT के मामले और 498A IPC /85 BNS के मामले शामिल हैं
- चेकबाउंस के मामले
- दुर्घटना क्लेम के मामले
- समझौता योग्य आपराधिक मामले
- भूमि अधिग्रहण के मामले
- सम्पति बंटवारा संबधित मामले
- बैंक रिकवरी एवं ऋण वसूली मामले।

निस्तारण वाले मामले
- बेदखली के मामले
- व्यावसायिक विवाद
- उपयुक्त सेवा मामलों के मामले
- श्रम अधिनियम के मामले
- अनुबंध अधिनियम के मामले
- उपभोक्ता मामले
- पारिवारिक विवाद से संबंधित से मामले

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:
न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्रधिकार
ए जी. ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची, फोन : 0651– 2481520, 2482392,
फैक्स : 0651– 2482397
अथवा
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, कोडरमा, पिन– 825410
सचिव 6200981332 कार्यालय दूरभाष : 6200937857
Email: dlsakoderma@gmail.com

कुमार शिवाशीष
पुलिस अधीक्षक–सह–सदस्य
जिला विधिक सेवा प्राधिकार
कोडरमा

उत्कर्ष गुप्ता
उपायुक्त–सह–उपाध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार
कोडरमा

रमाकान्त मिश्रा
प्रधान जिला न्यायाधीश–सह–अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकार
कोडरमा

निवेदक :
श्री गौतम कुमार
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कोडरमा

PR- 389821 (Law) 2026-27

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: ☎ 15100, DLSA कोडरमा हेल्पलाइन नंबर: ☎ 6200937857